1. पच्चीस वर्षों का नेतृत्व

परिचय

नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकारी नेतृत्व में गुजरात के मुख्यमंत्री और 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल शामिल है जिसमें उन्होंने शासन को कल्याण, बुनियादी ढाँचे एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ा है।

शासन और सेवा वितरण

- व्यक्तिगत अनुशासन में 20 साल तक काम पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिदिन साढ़े तीन से चार घंटे की नींद लेना और 10 दिनों से अधिक समय तक केवल पानी पीकर उपवास करना शामिल था।
- मेहसाना के 10 करोड़ रुपये के जिला सहकारी बैंक पायलट प्रोजेक्ट ने कृषि-घरेलू फीडर पृथक्करण को राज्यव्यापी स्तर पर लागू किया : तीन वर्षों के भीतर 1,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य।
- नर्मदा बांध ने नहरों और पाइपलाइनों के माध्यम से गुजरात में पेयजल के स्रोत को 80% भूजल से बदलकर 80% स्थलीय जल पर आधारित कर दिया है।
- गुजरात के पहले अंतर-बेसिन स्थानांतरण ने नर्मदा के अतिरिक्त जल को जल-संकटग्रस्त सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात की ओर मोड़ दिया।
- 'प्रवेशोत्सव' के तहत हर साल मानसून से पहले तीन दिनों तक प्रशासकों को जुटाया जाता था, जो कक्षा 1 में नामांकन के लिए रोजाना पाँच स्कूलों का दौरा करते थे।

गरिमा के साथ कल्याण

- भारत भर में निर्मित 12 करोड़ से अधिक शौचालय घरेलू स्वच्छता की कमी को दूर करके महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने में सहायक हैं।

- प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास सुरक्षा मजबूत होती है; उज्ज्वला योजना से महिलाओं की सुरक्षा में सुधार होता है, खाना पकाने के धुएँ और लगने वाले समय में कमी आती है।
- जल जीवन मिशन घरेलू नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराता है जिससे महिलाओं द्वारा प्रतिदिन पानी ढोने में लगने वाला समय कम हो जाता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) राहत ने लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा की रक्षा की।
- एक पेड़ माँ के नाम सार्वजनिक कार्यक्रमों में भावनात्मक भागीदारी को बढ़ावा देता है जिससे यह एक राष्ट्रव्यापी लोकप्रिय आंदोलन बन जाता है।
- गुजरात, पुणे और हैदराबाद स्थित दो दवा कंपनियों के एक दिवसीय दौरे ने स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन को प्रोत्साहित किया।

अवसंरचना और रणनीतिक क्षमता

- गुजरात में सूर्य की रोशनी वाले 300 दिन नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आधार प्रदान करते हैं; लिटिल रण ऑफ कच्छ परियोजनाओं से 200 गीगावाट सौर ऊर्जा का अनुमान है।
- सूर्य किरण-समृद्ध देशों के सहयोग के तहत पेट्रोलियम के लिए 'ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज' (OPEC) जैसा ही एक संगठन बनाने की परिकल्पना की गई।
- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इथेनॉल आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करके ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हैं।
- आत्मनिर्भर भारत खाद्य पदार्थों, दवाओं, रक्षा उपकरणों, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा एवं विनिर्माण में घरेलू क्षमताओं के माध्यम से स्वतंत्र विकल्पों को मजबूत करता है।
- विकास पथ, किसान पथ, प्रगति पथ, धर्म पथ नाम की सड़कें वंदे भारत और अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड रेल की पूरक हैं।
- मोदी 31 अक्टूबर, 2025 को केवडिया स्थित विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' में राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल हुए।

निष्कर्ष

नेतृत्व में सुनना, जिम्मेदारी सौंपना तथा परिणामों पर ध्यान देना शामिल है और आम लोगों के जीवन में सुधार अगले 25 वर्षों के लिए आधार प्रदान करता है।

2. प्रगति, समृद्धि और जन-केंद्रित शासन

परिचय

2001 के भूकंप के बाद शुरू हुई और 2014 के बाद भी जारी रही गुजरात की 25 साल की विकास यात्रा में औद्योगिक विकास, संस्थागत सुधार और कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं।

औद्योगिक विकास और निवेश

- गुजरात की 19 नीतियों में नई औद्योगिक नीति, 2026 भी शामिल है जो उद्योगों को पूंजी, ब्याज या बिजली सब्सिडी में से किसी एक को चुनने की अनुमति देती है।
- छह सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी मिली है; क्षेत्रीय नीतियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जहाज निर्माण को बढ़ावा देती हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी (सूर्य-समृद्ध), आईटी-सक्षम सेवाएँ (ITes), वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) और डेटा-सेंटर नीतियाँ उभरते उद्योगों का विस्तार करती हैं।
- धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (SIR) और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) भविष्योन्मुखी निवेश योजना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
- वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट सरल एकल-खिड़की अनुमोदन प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और आर्थिक सहयोग को सुगम बनाता है।
- छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति ने 6,077 प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट परियोजनाओं को समर्थन दिया है, जिसमें ₹2.50 लाख तक की सहायता प्रदान की गई।

संस्थागत सुधार और मानव पूंजी

- 2025 में स्थापित गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (GARC) संस्था ने सरल, प्रभावी और जवाबदेह प्रशासन की सिफारिश करते हुए छह रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।
- 2024 में स्थापित गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान (GRIT) संस्था विकसित गुजरात/2047 को व्यावहारिक विकास योजनाओं में परिवर्तित करती है।
- GRIT ने छह आर्थिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय आर्थिक मास्टर प्लान तैयार किए जिनमें बुनियादी ढाँचे, कौशल, निवेश एवं क्षेत्रीय शक्तियों को संरेखित किया गया।
- नमो लक्ष्मी योजना लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा का समर्थन करती है; नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना छात्रों को विज्ञान विषय में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में 13,353 क्लासरूम, 21,000 कंप्यूटर लैब, 109,000 स्मार्ट क्लासरूम और 5,000 विज्ञान-प्रौद्योगिकी-इंजीनियरिंग-गणित प्रयोगशालाएँ शामिल की गईं।

कल्याण और आवश्यक सेवाएँ

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम की सहायता राशि 5 लाख रुपये से बढ़कर 10 लाख रुपये हो गई, जिससे उपचार तक पहुँच का विस्तार हुआ।
- 29 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए; नमो श्री योजना गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सहायता को मजबूत करती है।

- ज्योतिग्राम योजना में 18,000 गाँवों में विद्युतीकरण किया गया; किसान सूर्योदय योजना के तहत 17,200 से अधिक गाँवों में दिन के समय बिजली की आपूर्ति की जाती है जिससे 21 लाख से अधिक किसानों को लाभ होता है।
- नल से जल योजना से आवश्यक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गुजरात भर में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए 100% घरों तक पहुँच हासिल की गई है।
- आर्थिक समावेशन ने 8.39 लाख लखपति दीदियों को सशक्त बनाया और प्राकृतिक खेती अपनाने वाले आठ लाख किसानों को सहायता प्रदान की।
- पीएम सूर्य घर योजना से 11.47 लाख रूफटॉप सोलर पैनल लगाने में मदद मिली, जिससे गुजरात के स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा मिला।

निष्कर्ष

विकसित गुजरात नागरिक कल्याण को क्षेत्रीय विकास एवं नवाचार से जोड़ता है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन और ब्लॉकचेन शामिल हैं।

3. सार्वजनिक सेवा के 25 वर्षों से प्राप्त अनुभव

परिचय

जन-केंद्रित शासन में गरिमा, सुलभता, जवाबदेही और विश्वास का संयोजन होता है जो नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक सेवा नेतृत्व में परिलक्षित होता है।

नागरिक-केंद्रित नेतृत्व

- एक कुशल नेतृत्व प्रशासनिक पहल को मान्यता देता है, नवाचार को प्रोत्साहित करता है और जमीनी हकीकतों की विस्तृत जानकारी के माध्यम से कार्यान्वयन को बनाए रखता है।
- गोधरा में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण औपचारिक रिपोर्टिंग चैनलों से परे स्थानीय नवाचार को मान्यता देते हुए, सक्रिय प्रशासनिक सहभागिता को दर्शाता है।
- प्रतिवर्ष लगभग 15 लाख तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने वाला पावागढ़ का महाकाली मंदिर स्थल स्थानीय विकास आवश्यकताओं के प्रति नेतृत्व के ध्यान को दर्शाता है।
- गोधरा ट्रेन दुर्घटना के दौरान, पीड़ित नागरिक के साथ सीधे संवाद ने अस्थिर परिस्थितियों के बीच सहानुभूति का प्रदर्शन किया।

समग्र विकास के लिए शिक्षा

- कर्मयोगी अभियान में लगभग 80,000 शिक्षक शामिल थे और सूरत व गांधीनगर में प्रत्यक्ष नेतृत्व की भागीदारी के माध्यम से शिक्षण क्षमता को मजबूत किया गया।
- 'वैष्णव जन तो' शिक्षकों की उस भूमिका को दर्शाता है, जिसमें वे सहानुभूतिपूर्ण आदर्श के रूप में कार्य करते हैं; वे शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ संवेदनशीलता और अच्छाई का भी मेल रखते हैं।
- चिल्ड्रेन्स यूनिवर्सिटी में सोच-समझकर तैयार किए गए शिक्षण वातावरण पर जोर दिया गया, जिसमें फर्नीचर, खिलौने, किताबें, भोजन एवं ऑडियो-विजुअल सामग्री को एकीकृत किया गया था।
- सप्त धारा ने संगीत, नृत्य, रंगमंच, योग, सामुदायिक सेवा, कला और कौशल के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दिया।
- गुजरात नॉलेज कंसोर्टियमइन पहलों और गुजरात क्विज ने अवसरों का विस्तार किया, जिससे छात्रों को अपनी क्षमताओं को खोजने और विकसित करने में मदद मिली।

मिशन-आधारित सार्वजनिक सेवा वितरण

- 2014 में रेड फोर्ट अभियान के माध्यम से शुरू की गई स्वच्छ भारत मिशन पहल में तकनीकी सहायता को व्यावहारिक परिवर्तन के साथ जोड़ा गया था।
- मन की बात के माध्यम से पोरबंदर और डांग स्वच्छता प्रयासों को मान्यता मिली, जिससे जिलों और कस्बों में भी इसे दोहराने के लिए प्रोत्साहन मिला।
- जन धन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने वित्तीय समावेशन का विस्तार किया, जिससे डिजिटल पहुँच के माध्यम से कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में सुधार हुआ।
- आकांक्षी जिले लक्षित विकास के माध्यम से ऐतिहासिक असमानता को दूर करने के लिए संयुक्त डेटा, माप, प्रतिस्पर्धा और केंद्रित प्रशासन का उपयोग करते हैं।
- निवारक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कल्याण केंद्र और एकीकृत चिकित्सा प्रणालियाँ सेवाओं को सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संवर्धन की ओर स्थानांतरित करती हैं।
- गुजरात का राजस्व विभाग भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करता है और विशिष्ट भूखंड पहचान का उपयोग करता है जिससे पारदर्शिता, पहुँच व लेन-देन की निश्चितता में सुधार होता है।

निष्कर्ष

शासन व्यवस्था मानवीय सेवा के माध्यम से 'सेवाश' को चरितार्थ करती है; श्री अरबिंदो और 'द मदर' के आदर्श, मानव एकता, बंधुत्व और सामंजस्य को 'वसुधैव कुटुंबकम' से जोड़ते हैं।।

4. सिविल सेवाओं के प्रदर्शन को बढ़ाना

परिचय

भुज भूकंप के बाद गुजरात में हुए सुधारों, 7 अक्टूबर, 2001 को नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने और 2014 से उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार पर, सिविल सेवा क्षमता विकसित भारत की नींव है।

क्षमता निर्माण संरचना का विकास

- मोदी के कार्यकाल के दो साल बाद शुरू हुए गुजरात के वार्षिक चिंतन शिविर ने वरिष्ठ नेतृत्व को तीन दिवसीय प्रशासनिक आत्म-परीक्षण करने में सक्षम बनाया।

- गुजरात ने 2001-2013 के संस्थागत सुदृढ़ीकरण के दौरान प्रक्रियात्मक अनुपालन की तुलना में परिणामों को प्राथमिकता देते हुए इलेक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण और ई-गवर्नेंस का विस्तार किया।
- 2 सितंबर 2020 को मिशन कर्मयोगी ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) की स्थापना की।
- भगवद् गीता का 'योगः कर्मसु कौशलम्' NPCSCB के नियम-आधारित कार्मिक प्रशासन से भूमिका-आधारित क्षमता निर्माण की ओर बदलाव का मार्गदर्शन करता है।
- क्षमता निर्माण आयोग (CBC) मानक तय करता है; कर्मयोगी भारत निरंतर सीखने के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (iGOT) कर्मयोगी संचालित करता है।

योग्यता-आधारित शिक्षण की बुनियाद, 2020-2025

- क्षमता निर्माण योजनाएँ (CBPs) विभागीय अधिगम की जरूरतों की पहचान करती हैं; कर्मयोगी सक्षमता मॉडल सक्षमता की साझा परिभाषाएँ निर्धारित करता है।
- 2022 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान मानक (NSCSTI) उपायों का उद्देश्य प्रत्यायन एवं संस्थागत सुधार को मानकीकृत करना है।
- अक्टूबर 2024 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह पहल निरंतर सीखने को प्रोत्साहित करती है; वहीं राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा सहानुभूति को बढ़ावा देती है।
- 2025 के अंत तक, iGOT के शिक्षार्थियों की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक हो गई, आठ करोड़ लोगों ने कोर्स पूरे किए और 4,600 से अधिक कोर्स संचालित हैं, जिससे बहुभाषी शिक्षा का विस्तार हुआ।

संस्थागतकरण एवं प्रदर्शन, 2026

- प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद (PMHRC) इकाई रणनीति का निर्देशन करती है; कैबिनेट सचिवालय समन्वय इकाई सरकार-व्यापी कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- अप्रैल 2026 साधना सप्ताह में संस्थागत परिवर्तन की मांग की गई; हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह में तीन करोड़ लोगों ने शिक्षा पूरी की।
- मई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन ने सरकार और प्रशिक्षण संस्थानों को आपस में जोड़ा, जिससे संस्थागतकरण व प्रदर्शन-आधारित शासन को बढ़ावा मिला।
- उन्नति (UNNATI) साझा संसाधनों और सहयोग के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ता है; इसका क्षमता सूचकांक लक्षित संस्थागत सुधार का समर्थन करता है।
- सीबीपी (CBP) विभागीय प्राथमिकताओं के साथ पाठ्यक्रम, संकाय विकास और प्रशिक्षण कैलेंडर को संरेखित करता है, मांग-आधारित योजना और प्रासंगिक शिक्षण का समर्थन करता है।
- iGOT और इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (eHRMS) के साथ एकीकरण अधिगम, पेशेवर रिकॉर्ड और कार्यबल नियोजन को जोड़ता है।

निष्कर्ष

क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यक्तिगत दक्षताओं के साथ-साथ संस्थागत प्रक्रियाओं और कार्यस्थल संस्कृति में भी बदलाव लाना आवश्यक है जिससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग, मानवीय निर्णय एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

5. विकसित भारत के लिए भारत का परमाणु मंथन

परिचय

भारत की परमाणु नीति स्वच्छ ऊर्जा को विश्वसनीय प्रतिरोध के साथ संयोजित करती है; दिसंबर 2025 में पारित भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन एवं विकास (शांति अधिनियम) इस ढाँचे को आगे बढ़ाता है।

परमाणु नीति का विकास

- 1947 में आजादी के बाद होमी जे. भाभा के नेतृत्व में स्वदेशी परमाणु विकास को सक्षम बनाने वाला परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1948 लागू हुआ।
- राजस्थान के पोखरण में 1974 में हुए शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (PNE) ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक प्रतिबंधों को प्रेरित किया।
- अटल बिहारी वाजपेयी का 27 मई, 1998 का बयान पोखरण-II परीक्षणों के बाद आया, जो 11-13 मई को हुए थे, जिसमें उन्होंने संप्रभु सुरक्षा की पुष्टि की थी।
- वाजपेयी ने 13 मई, 1998 को बिल क्लिंटन को लिखे अपने पत्र में निवारण को 1962 की आक्रामकता और पड़ोसी देशों के परमाणु सहयोग से जोड़ा था।
- राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जुलाई 2005 के 123 समझौते ने फ्राँस, रूस एवं कनाडा से रिएक्टर और ईंधन के आयात को संभव बनाया।
- पृथक्करण योजना, जिस पर अगस्त 2005 से फरवरी 2006 के बीच बातचीत हुई, में भारत के 2005 में दर्ज किए गए 22 परमाणु संयंत्रों वाले कार्यक्रम को संबोधित किया गया था।

ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी क्षमता

- परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करना है जो ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक शुद्ध शून्य ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- परमाणु विखंडन विश्वसनीय आधारभूत बिजली प्रदान करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का पूरक है और बढ़ती विकासात्मक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

- दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (PHWR), लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR), फास्ट ब्रीडर और थोरियम तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हैं।
- शांति कार्यक्रम अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, वित्त, बीमा एवं कौशल के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का विस्तार करता है जिससे घरेलू परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है।
- परमाणु ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-सक्षम परमाणु एवं विकिरण प्रौद्योगिकियों के लिए मजबूत नियामक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

सुरक्षा एवं विनियामक प्रावधान

- समृद्ध एवं समस्थानिक पृथक्करण जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया जाए, ये अधिकार केंद्र सरकार या पूर्णत: स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
- आरक्षित ईंधन-चक्र गतिविधियों में प्रयुक्त ईंधन का पुनर्संसाधन, पुनर्चक्रण, रेडियोन्यूक्लाइड पृथक्करण, उच्च-स्तरीय अपशिष्ट प्रबंधन और भारी जल उत्पादन/उन्नयन शामिल हैं।
- शांति संस्थागत निगरानी को मजबूत करने के लिए लाइसेंसिंग और सुरक्षा प्राधिकरणों की एक व्यवस्थित रूपरेखा स्थापित करता है जिसमें लाइसेंस देना, निलंबन और रद्द करना शामिल है।
- परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में मुआवजा सुनिश्चित किया गया; शांति (SHANTI) ने श्रेणीबद्ध, स्थापना-विशिष्ट ऑपरेटर दायित्व की शुरुआत की।

निष्कर्ष

शांति परियोजना परमाणु विस्तार को तकनीकी आत्मनिर्भरता, संस्थागत निगरानी एवं सुरक्षा से जोड़ती है ताकि एक कुशल व सुरक्षित परमाणु पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन किया जा सके।

6. वाइब्रेंट गुजरात से विकसित भारत तक

परिचय

विकसित भारत@2047 को कौशल, क्षमता और समावेशी समृद्धि में तब्दील होने के लिए निवेश की आवश्यकता है; सबका प्रयास और विकसित भारत@2047 : युवाओं की आवाज सामूहिक भागीदारी पर जोर देती है।

योग्यता से लेकर क्षमता तक

- 2003 में शुरू हुई वाइब्रेंट गुजरात ने निवेश आकर्षित किया। सतत विकास के लिए ऐसी मानवीय क्षमताओं की आवश्यकता होती है जो नवाचार एवं रोजगार उत्पन्न कर सकें।
- डिग्री अध्ययन को प्रमाणित करती है, कौशल कार्य निष्पादन को सक्षम बनाता है और क्षमता स्वतंत्र अनुप्रयोग एवं समस्या-समाधान को सक्षम बनाती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 योग्यता, बहुविषयक शिक्षा, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और अनुभवात्मक शिक्षा को प्राथमिकता देता है।
- गुजरात द्वारा 2021 में स्थापित कौशल्या : कौशल विश्वविद्यालय संस्था शिक्षा को कार्य से जोड़ती है जिससे युवा 'कौशल-स्मार्ट' बनते हैं।

उद्योग से जुड़ा कौशल विकास

- गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (GSFC) के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल ने उद्योग-संरेखित जीएसएफसी विश्वविद्यालय की स्थापना की।
- अनिवार्य छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम (SIP) प्रत्येक सेमेस्टर में इंटर्नशिप प्रदान करता है; मेडिकल कॉलेज से प्रेरित शिक्षण पद्धति गैर-चिकित्सा संबंधी अनुभवात्मक शिक्षा को मजबूत करती है।
- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (2024) का लक्ष्य पाँच वर्षों में 12 महीने के सवैतनिक रोजगार के माध्यम से एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।
- नमो गुजरात कौशल्या एवं रोजगार मिशन (NGKRM) को उद्योग से जुड़े कौशल विकास, उन्नत कौशल विकास और नए कौशल विकास के लिए 2026-27 में ₹226 करोड़ प्राप्त हुए।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना सेवाओं के क्षेत्र में भी विस्तार कर रही है जिसके तहत प्रशिक्षण को अनुभव में परिवर्तित करते हुए प्रति माह ₹3,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।
- नमो कौशल्या लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) शिक्षा एवं तकनीकी भागीदारी को समर्थन देने के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

हितधारकों की जिम्मेदारियाँ

- सरकार नीति, अवसंरचना, संस्थानों, संसाधनों व अवसरों के माध्यम से मानव पूंजी विकास को सक्षम बनाती है और एक समन्वित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है।
- उद्योग पाठ्यक्रम को आकार देता है, इंटर्नशिप एवं अप्रेंटिसशिप प्रदान करता है, युवाओं का मार्गदर्शन करता है और व्यावहारिक अनुसंधान का समर्थन करता है जिससे रोजगार के रास्ते मजबूत होते हैं।
- उच्च शिक्षा संस्थान समस्या-समाधान, रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता एवं नवाचार का विकास करता है और पारंपरिक ज्ञान प्रसारण से परे आजीवन सीखने को समाहित करता है।
- छात्र एवं युवा में निरंतर सीखने, प्रयोग करने व कौशल हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही, वास्तविक दुनिया के संदर्भों में ज्ञान को लागू करना भी आवश्यक है।
- समाज शिक्षा को सार्थक आर्थिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान करता है और साझा जिम्मेदारी के माध्यम से मानव-पूंजी विकास को मजबूत करता है।

निष्कर्ष

वाइब्रेंट गुजरात से विकसित गुजरात और विकसित भारत@2047 की ओर प्रगति निवेश को क्षमता, नवाचार एवं समावेशी समृद्धि में परिवर्तित करने पर निर्भर करती है।

7. आयुष्मान भारत : स्वास्थ्य की पुनर्कल्पना

परिचय

2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना वित्तीय सुरक्षा, प्राथमिक देखभाल, बुनियादी ढाँचा और डिजिटल स्वास्थ्य को एकीकृत करती है; 1.8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर समुदायों को व्यापक देखभाल के करीब लाते हैं।

बीमा कवरेज और पहुँच

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) सबसे गरीब 40% लोगों को लक्षित करते हुए ₹5 लाख का वार्षिक पारिवारिक बीमा प्रदान करती है।
- एबी-पीएमजेएवाई योजना 55 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँची है; 47 करोड़ से अधिक कार्डों के माध्यम से 13 करोड़ से अधिक प्रवेशों को अधिकृत किया गया, जिनकी कीमत 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
- सूचीबद्ध 38,374 अस्पतालों में, जिनमें से लगभग आधे सार्वजनिक/निजी हैं, कैशलेस देखभाल 27 चिकित्सा विशिष्टताओं को कवर करने वाले 1,961 पैकेज प्रदान करती है।
- इस योजना में पश्चिम बंगाल को 2026 में शामिल किए जाने से 36 राज्यों/क्षेत्रों का कवरेज पूरा हो गया; अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी से ₹8,831 करोड़ मूल्य के 30.46 लाख उपचार संभव हो सके।
- अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आय-स्वतंत्र कवरेज प्रदान किया, जिसका लक्ष्य 4.5 करोड़ परिवारों के छह करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाना था।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना

- 2021 में शुरू की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) योजना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) के माध्यम से सहमति-आधारित रिकॉर्ड रखने में सक्षम बनाती है।
- ABDM में 97 करोड़ से ज़्यादा ABHA नंबर और 116 करोड़ से ज़्यादा लिंक्ड रिकॉर्ड मौजूद हैं जबकि 2025 की शुरुआत में यह संख्या 50 करोड़ रिकॉर्ड थी।
- स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री ने 5.70 लाख से अधिक सुविधाओं और 10.83 लाख पेशेवरों को अपने साथ जोड़ा है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय (NHCX) दावों के प्रसंस्करण को मानकीकृत करता है; स्वास्थ्य सूचना विनिमय और सहमति प्रबंधक सहमति-आधारित डेटा-साझाकरण को नियंत्रित करता है।
- जून 2026 का यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (UHI) इंटरऑपरेबल ऐप्स के माध्यम से सत्यापित डॉक्टरों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं एवं ब्लड बैंकों को जोड़ता है।
- भारत स्वास्थ्य शब्दावली सेवा (BHTS) स्वास्थ्य-रिकॉर्ड शब्दावली का मानकीकरण करता है; आरोग्य सेतु अब ABHA से जुड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड का प्रबंधन करता है।

वित्तीय सुरक्षा और समावेशन

- 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) योजना के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए ₹64,180 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- 1.32 करोड़ से अधिक वय वंदना कार्डों के माध्यम से 19.64 लाख से अधिक रोगियों को भर्ती कराया गया, जिनमें 4,394 करोड़ रुपये से अधिक के अधिकृत उपचार शामिल हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों के बीमा कवरेज में लगभग 15% से लेकर 50% से अधिक की वृद्धि हुई; महिलाओं को लगभग आधे कार्ड और 48% से अधिक उपचार प्राप्त हुए।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में 64.2% (2013-14) से 43.4% (2022-23) की गिरावट दर्ज की गई है; आर्थिक सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार लाभार्थियों को ₹1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत होगी।
- लैंसेट रीजनल हेल्थ (दक्षिण-पूर्व एशिया) रिपोर्टों के अनुसार, लाभार्थियों में समय पर कैंसर उपचार शुरू करने की दर में 90% की वृद्धि हुई है जबकि गैर-लाभार्थियों में यह वृद्धि 33% है।
- इस समन्वय में 56 राज्य स्वास्थ्य योजनाएँ शामिल हैं और साझा प्लेटफार्मों के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं एवं कमजोर समूहों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

निष्कर्ष

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए मजबूत देखभाल की गुणवत्ता, धोखाधड़ी नियंत्रण और डेटा गोपनीयता की आवश्यकता होती है जो जवाबदेह प्रशासन एवं समन्वित राष्ट्रीय-राज्य कार्यान्वयन द्वारा समर्थित हो।

8. भारत का हरित परिवर्तन

परिचय

भारत का विकसित भारत 2047 की ओर संक्रमण, 2021 में पार्टियों के 26वें सम्मेलन (COP 26) में की गई प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित, संधारणीयता को प्रतिस्पर्धात्मकता, निवेश और रोजगार से जोड़ता है।

स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक संक्रमण

- राष्ट्रीय सौर मिशन (2010), नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व, हरित ऊर्जा खुली पहुँच नियम और हरित ऊर्जा गलियारे नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करते हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) कृषि में सौर ऊर्जा का विस्तार करते हुए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देता है।

- उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (PLI) से घरेलू विनिर्माण एवं स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिलती है।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पीएटी) को लागू करता है जिससे ऊर्जा-गहन उद्योगों की संसाधन उत्पादकता में सुधार होता है।
- 'सभी के लिए किफायती प्रकाश उत्सर्जक डायोड द्वारा उन्नत ज्योति' (उजाला) ऊर्जा-कुशल घरेलू प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 50 लाख टन उत्पादन करना है : इसमें 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 19,744 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

जलवायु प्रतिबद्धताएँ और जल सुरक्षा

- COP26 के पंचामृत कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 50% नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके।
- पंचामृत ने एक अरब टन उत्सर्जन में अनुमानित कमी, आर्थिक कार्बन तीव्रता में 45% की कमी और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का संकल्प लिया है।
- पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन (LiFE) जिम्मेदार उपभोग, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ गतिशीलता और सामुदायिक संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल सुरक्षा का समर्थन करती हैं।
- अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, भूजल पुनर्भरण, जलसंभर विकास, वर्षाजल संचयन और कुशल सिंचाई जैसी चीजें स्थानीय योजना के माध्यम से मीठे पानी पर निर्भरता को कम करती हैं।

संसाधन दक्षता और टिकाऊ शहर

- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC) और इको निवास संहिता भवन निर्माण की दक्षता को मजबूत करती है जिससे खपत और उत्सर्जन में कमी आती है।
- अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) 2.0 और स्मार्ट सिटी मिशन संसाधन-कुशल शहरों का समर्थन करता है।
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरे और अन्य प्रकार के कचरे के प्रबंधन में जवाबदेही को मजबूत करता है जिससे चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।
- पुनर्चक्रित सामग्री मानक, पुनर्चक्रण अवसंरचना, अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ताओं का औपचारिक एकीकरण और डिजिटल ट्रैकिंग से सामग्री-पुनर्प्राप्ति की व्यवहार्यता में सुधार होता है।
- राष्ट्रीय सतत आवास मिशन लचीले शहरी विकास का समर्थन करता है; वन एवं आर्द्रभूमि गर्मी, बाढ़ व जल संकट जैसी समस्याओं का समाधान करते हैं।
- सतत वित्त, मापने योग्य लक्ष्य, पारदर्शी निगरानी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय किफायती हरित प्रौद्योगिकियों को निवेश योग्य और सुलभ बनाते हैं।

निष्कर्ष

हरित विकास के लिए किफायती प्रौद्योगिकियों, समन्वित कार्यान्वयन और जलवायु लचीलेपन की आवश्यकता होती है; हरित हाइड्रोजन इस्पात, उर्वरक, शोधन, जहाजरानी और भारी परिवहन को कार्बन मुक्त कर सकता है।